हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 13 | देहरादून, बुधवार, 29 जून, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर केदारनाथ धाम में मानसून में भी जारी रहेंगी हेली सेवाएं 5

शिलान्यास यदि हमारी सरकार में हुआ है तो उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार करेगी : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्द एवं बैरक का शिलान्यास किया , इस दौरान मुख्यमंत्री ने हीरो मोटोकॉर्प लि. द्वारा सीएसआर मद से उत्तराखंड पुलिस को प्रदान की गई 150 चीता मोबाइल बाइक का फ्लैग ऑफ किया।

इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन, कार्ग क्वार्टर गार्द एवं बैरक का शिलान्यास पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा आज शिलान्यास के साथ ही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही लंबे समय से एक मांग पूरी हुई है।

राज्य सरकार का यह संकल्प है कि किसी भी कार्य योजना का शिलान्यास यदि हमारी सरकार में हुआ है तो उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में होगा। इस निर्माण कार्य के पूर्ण होते ही पुलिस जवानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा, अच्छे रहन-सहन के साथ अच्छी सेवाएं हमारे जवान इस राज्य को दें ऐसी अपेक्षा करता हूं। इस पुलिस लाईन के कार्मिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं सुविधायुक्त होगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था व पुलिस विभाग से कहा कि नवीन आधुनिक भवन समस्त आधारभूत सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। उन्होंने निर्माण के दौरान गुणवत्ता को लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात कही साथ ही निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा की जनपद देहरादून में राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके लिए राज्य की पुलिस लाईन में उच्च कोटि के प्रशासनिक भवन की आवश्यकता होती है, राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अत्यधिक पुलिस बल एवं पीएसी व्यवस्थापन होने के कारण पुलिस लाइन, देहरादून में पुलिस बल का अत्यधिक दबाव बना रहता है, जिसके लिए अतिरिक्त बैरक के निर्माण किया जाना आवश्यक है।

इस दौरान सरकार द्वारा पुलिस कल्याण हेतु किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार के गृहमंत्री जी के द्वारा आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ओर से रू0 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करायी गयी है। वाहनों के क्रय हेतु भी रू0 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। चीता पुलिस को आधुनिक बनाने हेतु लगभग रू० 3 करोड़ के स्मॉल आर्मस् क्रय किये गये है। कोविड के दौरान सरकार द्वारा फ्रन्ट लाईन वॉरियर होने के कारण प्रत्येक पुलिस कर्मी को रू 10 हजार प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। कर्मचारियों के कल्याण हेतु रू0 2.5 करोड़ का भी बजट में प्रावधान किया गया है। अपराधियों को दण्डित/गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस कर्मियों को दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि में भी बढ़ोतरी की गयी है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में नियुक्त हेड कानि० / कानि० एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी किट के स्थान पर क्रमशः ₹ 2250 व ₹ 1500 प्रति वर्ष वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है। जिसमें शीघ्र ही और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा जीवन रक्षक निधि के अन्तर्गत 10 सेवारत पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रित सदस्यों को उपचार हेतु रु 30.40 लाख अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई। पुलिस शहीद कोष के अंतर्गत कुल 14 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रु० 1-1 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस कार्मिकों की पदोन्नति एवं भर्ती कार्य के संबंध में अवगत करवाया की मृतक आश्रित में 13 अभ्यर्थियों को सेवायोजन प्रदान किया गया। मुख्य आरक्षी ना०पु० / अभिसूचना / पीएसी/स०पु० के रिक्त 723 पदों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया है। पुलिस लिपिक संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है। उप निरीक्षक ना०पु० / अभिसूचना / पीएसी एवं फायर सर्विस द्वितीय अधिकारी के 221 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के दृष्टिगत आरक्षी ना०पु०/अभिसूचना / पीएसी / फायर सर्विस के 1521 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी तथा इस हेतु 17 भर्ती केन्द्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही प्रचलित है। उन्होंने बताया मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार के रिक्त 272 पदों पर सीधी भर्ती हेतु की गयी विज्ञप्ति पर लिखित परीक्षा इस माह जुलाई-2022 में प्रस्तावित है। इन सभी परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व उत्तराखंड अधीन...

तरक्की पर है उत्तराखंड, जल्द बनेंगे वर्चुअल पुलिस थाने, मिलेगी सुविधा E-FIR की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड वासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी. इसमें कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. सूत्रपातके समय वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी फिर धीरे-धीरे कर अन्य संबंधों को भी जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतीकरण दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है. सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-एफआईआर से आमजन को बहुत सुविधा होगी. व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा. ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए.मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है. ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है. इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए.सीएम ने बताया गया कि ई-एफआईआर के लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है. शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाइल एवं वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा. ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा. जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी. शिकायत करने वाले को इसकी रिसीविंग भी मिल जाएगी. यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा. ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा.

युवाओं को देख 70 साल की दादी को आया जोश, हरकी पैड़ी पर पुल से लगा दी छलांग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार। हरकी पैड़ी स्थित पुल से गंगा में छलांग लगाते हुए 70 साल से अधिक उम्र की दादी का स्टंट सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया है। दादी हरियाणा के जींद की बताई जा रही हैं। दादी गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंची थीं। पुल से युवाओं को गंगा में छलांग लगाते हुए दादी भी जोश में आ गईं। दादी ने उफनती गंगा में छलांग दी और तैरकर आसानी से घाट के किनारे पहुंच गई।

सूट-सलवार पहने और मेहंदी से रंगे बालों वाली दादी का स्टंट व जोश देखकर हर कोई हैरान है। वायरल वीडियो में हरकी पैड़ी के पास कांगड़ा घाट को जोड़ने वाले आर्च पुल पर कुछ युवा गंगा में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। युवाओं से बात करने के बाद दादी को भी जोश आ जाता है। एक युवक दादी से गंगा की मुख्य धारा में कूदने के लिए इशारा करता है।

युवक से बात करते हुए दादी पुल की रेलिंग को लांघकर सीधे गंगा में कूद जाती हैं। दादी के गंगा में कूदते हुए पुल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 24 सेकेंड की वीडियो में दादी गंगा में कूदने के बाद आसानी से तैरकर घाट के किनारे पहुंच जाती हैं। दादी के स्टंट का वीडियो चंद सेकेंड में सोशल मीडिया पर छा गया। वीडियो वायरल करने वाले ने कैप्शन दिया है 'हमारी दादी क्या छोरों से कम हैं'।

बताया जा रहा है दादी के साथ आए उनके किसी परिचित ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। हरकी पैड़ी पर पुलिस का पहरा रहता है।

गंगा में स्नान करने या स्टंट के दौरान डूबने से अक्सर श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। दादी के स्टंट के बाद पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

दुनिया का सबसे महंगा तकिया, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, बनाने में लगे 15 साल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

एक डच सरवाइकल विशेषज्ञ से डिज़ाइनर बने एक शख्स ने दुनिया के सबसे महंगे तकिए (world's most expensive pillow) को बनाया और डिजाइन किया है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ₹टेलरमेड पिलो₹ (Tailor Made Pillow) दुनिया का सबसे विशिष्ट और उन्नत तकिया है. यह मिस्र के कपास और शहतूत रेशम से बना है और गैर विषैले डच मेमोरी फोम से भरा है. नीदरलैंड के थिज वैन डेर हिल्स्ट ने तकिए का निर्माण किया है, जो आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के अनुसार $ 57,000 (लगभग ₹ 45 लाख) में बिकता है.

वेबसाइट के मुताबिक, हिल्स्ट को इस खास तकिए को बनाने में 15 साल लगे. यह 24 कैरेट सोने, हीरे और नीलम से जड़ा हुआ है. इसके अलावा, तकिए को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपास रोबोट मिलिंग मशीन से आता है.

तकिए में 24 कैरेट सोने का आवरण होता है - एक चमकदार कपड़े का कवर जो सुरक्षित और स्वस्थ नींद के लिए सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कथित रूप से अवरुद्ध करता है. मूल्य टैग में जोड़ने के लिए एक ज़िप है जिसमें 22.5 कैरेट का नीलम और चार हीरे हैं.वेबसाइट के अनुसार, ₹हाई-टेक समाधानों और पुराने जमाने की शिल्प कौशल का मेल, टेलरमेड पिलो अब तक का सबसे नवीन और सभी व्यक्तिगत तकिए से ज्यादा बेहतर है.₹तकिए को एक ब्रांडेड बॉक्स में पैक किया जाता है.

हिल्स्ट का दावा है कि तकिया अनिद्रा से पीड़ित लोगों को शांति से सोने में मदद करेगा. वेबसाइट ने बताया कि तकिया प्रत्येक ग्राहक के लिए कस्टम-मेड है.3डी स्कैनर का उपयोग करके व्यक्ति के कंधों, सिर और गर्दन के सटीक आयामों को सावधानीपूर्वक मापा जाता है. इसके बाद, यह एक डच मेमोरी फोम से भर जाता है, जो हाई-टेक रोबोटिक मशीन मिलों का उपयोग करके व्यक्ति के सिर के आकार के अनुकूल हो जाता है.

तकिए बनाने से पहले ग्राहक के शरीर के ऊपरी हिस्से का नाप और सोने की मुद्रा भी नोट कर ली जाती है.कंपनी ने कहा है, ₹इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, पुरुष या महिला, साइड या बैक स्लीपर. आपका टेलरमेड तकिया आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है. "

क्या आप जानते हैं नैनीताल के मशहूर ब्रिटिशकालीन बोट हाउस क्लब का इतिहास ?

फ़िरोज़ आलम 'गाँधी' की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नैनीताल के मल्लीताल में स्थित बोट हाउस क्लब ब्रिटिशकालीन है. वहीं, करीब 125 साल पुराना यह क्लब पर्यटकों को काफी लुभाता है... इस क्लब में कई सुपर हिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जिसमें राजेश खन्ना की 'कटी पतंग', रितिक रौशन की 'कोई मिल गया', डीनो मौर्या की 'बाज द बर्ड इन डेंजर', वहीदा रहमान की शगुन, राजेश खन्ना की जाना, नसीरुद्दीन शाह की मासूम आदि प्रमुख हैं । बोट हाउस क्लब के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इसका अस्थाई निर्माण 1892 में किया गया था । यहां, 1880 के विनाशकारी भूस्खलन से पहले माँ नारायणी देवी का मंदिर था । इतिहासकारों के अनुसार, क्लब के निर्माण के बाद वर्ष 1897 में इसके मुख्य भवन का निर्माण हुआ था ।

हालांकि वर्तमान में बोट हाउस क्लब की सदस्यता के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है.... सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल में स्थित बोट हाउस क्लब (Boat House Club Nainital) ब्रिटिशकालीन है.... लगभग 125 साल पुराना यह क्लब पर्यटकों को काफी लुभाता है... क्लब से केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े उद्योगपति भी जुड़े हैं.... हाल ही में इस क्लब के लिए सदस्यता और विजिटिंग मेंबर को लेकर नियम बदले गए हैं.. बोट हाउस क्लब के साथ ही नैनीताल यॉट क्लब भी जुड़ा है.... यह क्लब सेलिंग से जुड़ी प्रतियोगिताएं करवाता रहा है....

वर्तमान में बोट हाउस क्लब की सदस्यता के लिए यहां के पदाधिकारियों ने दशकों बाद नियमों में कुछ बदलाव किया है.... क्लब की आजीवन सदस्यता के नियम को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा विजिटिंग मेंबर की एंट्री पर भी अब रोक लगा दी गई है.... सदस्यता के लिए तीन साल उम्र घटा दी गई है.... पहले जहां 21 साल की उम्र में सदस्यता मिलती थी, वह अब घटकर 18 साल कर दी गई है.. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्लब मेंबर बनाने की नई शुरुआत की गई है.... लगभग 60 हजार की पेंशन वाले कर्मचारियों को सदस्यता के लिए 40 फीसदी फीस जमा करनी होगी.... इसके अलावा अभी तक पूरे साल में क्लब के विकास को लेकर केवल 2.5 लाख रुपये ही खर्च किए जा सकते थे,... लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया गया है....

सदस्यता शुल्क में नहीं हुआ है बदलाव

बोट हाउस क्लब पदाधिकारी बताते हैं कि क्लब की सदस्यता के लिए स्क्रीनिंग मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जो आवेदक की जांच करेगी. उनके बैकग्राउंड को ठीक तरह से देखेगी और उसके बाद ही उन्हें मेंबरशिप दी जाएगी. यहां की सदस्यता के लिए सालाना तीन लाख रुपये शुल्क लिया जाता है, जिसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.झील के किनारे बने नैनीताल बोट हाउस क्लब में लाइब्रेरी, बार, रेस्टोरेंट, बिलियर्ड आदि की सुविधाएं क्लब से जुड़े सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं.

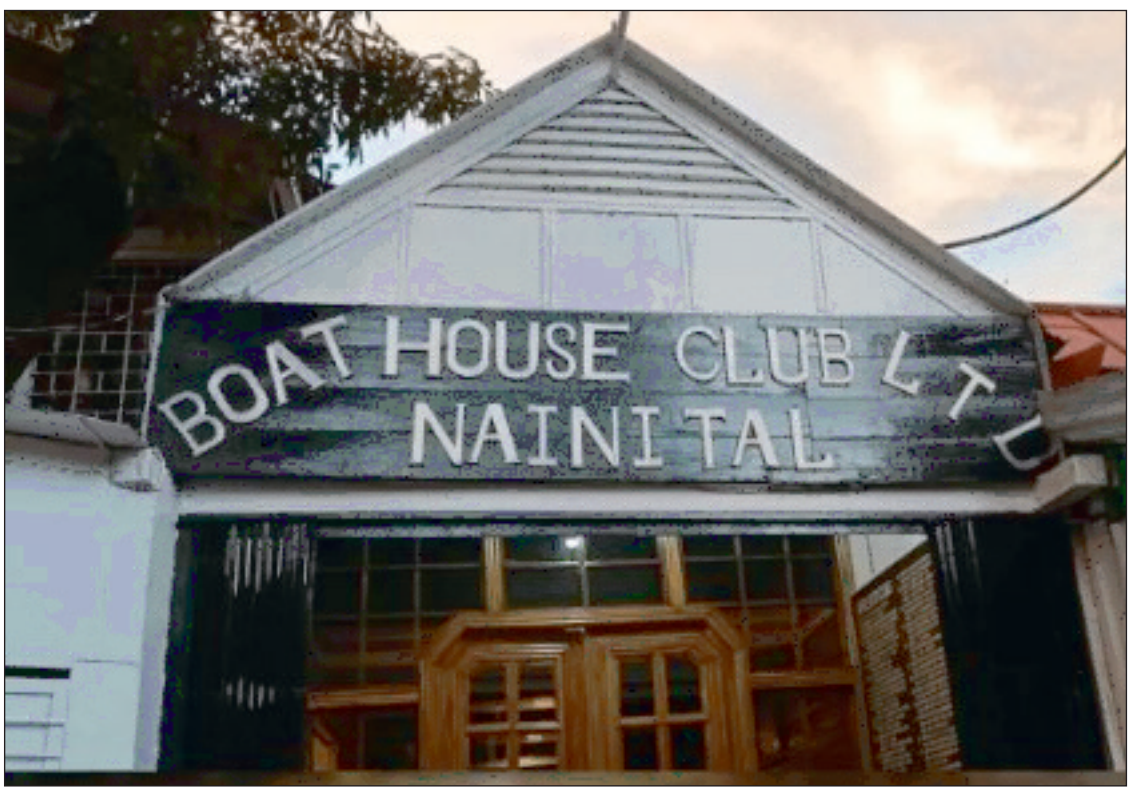

चाइल्ड फ्रेंडली सिटी का सपना जल्द होगा साकार : डॉ आर. राजेश कुमार, DM देहरादून

फिरोज़ आलम
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फेन्डली सिटी परियोजना को साकार करने के लिए मंगलवार को देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 ने हिन्दुस्तान स्टीलवकर्स कंस्ट्रक्शन लि0 के साथ MOU साइन किया है । इसके इस प्रक्रिया के बाद उम्मीद की जा रही है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी परियोजना का का मिशन तेज़ी से कामयाबी की ओर बढ़ेगा और देहरादून के लोगों को एक अद्भुत स्मार्ट सिटी का सपना धरातल पर साकार होता नज़र आएगा।

देहरादून के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून डा0 आर राजेश कुमार ने कहा की परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र ही धरातल पर किया जाएगा जिसके पश्चात देहरादून शहर के स्कूली बच्चों एवं नागरिकों सहज एवं सुरक्षित आवागमन का अवसर मिलेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चाइल्ड फेन्डली सिटी परियोजना (सीटीस) का उद्देश्य शहर की योजना, रचना एवमं कार्यान्वन में बच्चों को प्राथमिकता देना है, जिससे शहर में बच्चों का आवागमन स्कूल से घर एवं दूसरे स्थानो हेतु आसान व सुरक्षित बनाया जा सके इस परियोजना को भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीयन यूनियन, तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा समर्थन प्राप्त है।इस कार्य हेतु देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ए०बी०डी० क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ एवं स्कूल को बच्चों के अनुकूल डिजाइन किया जायेगा। आपको यहाँ बता दें कि इस परियोजना में अभी तक ए०बी०डी० क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 34 स्कूलों के विद्यार्थियों (लगभग 22000), अभिभावकों, शिक्षकों, दुकानदारों एवं पैदल यात्रीयों के साथ मिलकर सर्वे करवाया गया जिसमे बच्चों के आवागमन सम्बंधित चुनौतियों का अध्ययन किया गया।देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चाइल्ड फेन्डली सिटी परियोजना (सीटीस) के अन्तर्गत देहरादून शहर में स्मार्ट रोड के अतिरिक्त 6 कि0मी0 का स्ट्रेच को भी कवर किया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी परियोजना (सीटीस) की डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है तथा शीघ्र ही परियोजना धरातल पर आरम्भ कर दी जाएगी जिसकी पूर्ण होने की समय सीमा लगभग 18 माह है।

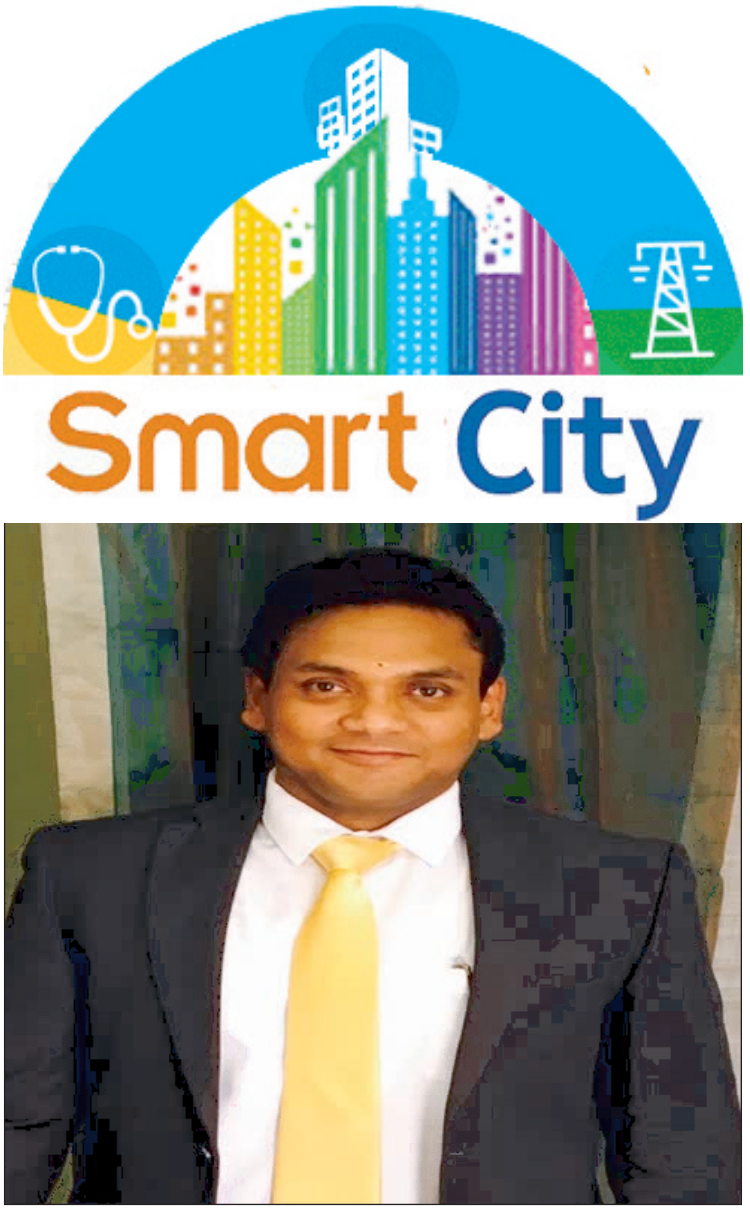

घर बैठे दर्ज़ होगी एफआईआर, देवभूमि मोबाईल एप से भी जोड़ा जाएगा : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारम्भ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलोजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए। बताया गया कि ई-एफआईआर के लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है। शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाईल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी। शिकायत करने वाले को इसकी पावती मिल जाएगी। यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जाएगी। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाईल एप से भी जोड़ा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, एडीजी वी मुरूगेशन, आईजी बिमला गुन्ज्याल, अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल, सहित गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

आकाश अंबानी बने रिलायंस जियो के चेयरमैन, मुकेश अंबानी ने दिया इस्तीफा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में गैर-कार्यकारी निदेशक, आकाश अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रिलायंस जियो ने एक बयान में कहा कि 27 जून, 2022 को हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुकेश अंबानी ने 27 जून से कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बैठक के परिणामों में पंकज पवार की पांच साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति भी थी, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन थी। कंपनी बोर्ड ने रामिंदर सिंह गुजराल और के.वी. चौधरी को पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

रिलायंस जियो में, आकाश अंबानी उत्पादों और डिजिटल सेवाओं के अनुप्रयोगों के विकास में निकटता से शामिल रहे हैं। उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एक प्रमुख के साथ स्नातक किया।बाजार विशेषज्ञ प्रकाश दीवान ने कहा कि यह कदम कंपनी की आईपीओ की योजना के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ₹शायद नए नेतृत्व के साथ रोलआउट किया जाएगा। यह रिलायंस जियो आईपीओ के लिए बहुत ही निर्णायक रूप से एजेंडा निर्धारित करता है।₹उन्होंने कहा, ₹मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट कदम है और व्यवसाय जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से चलता है,₹ उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुधवार के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी से उछाल आएगा।

पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को यह दस्तावेज जमा करने होंगे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के तहत ऐसे किसान परिवारों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना को अगले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। यह योजना पूरी तरह से सरकार समर्थित है और जोत वाले सभी किसानों के परिवारों पर लागू होती है। पीएम-किसान योजना के तहत, भूमि धारक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ मिलता है, जो चार महीने के अंतराल में साल में तीन बार वितरित किया जाता है। अब तक, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पीएम-किसान योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है

प्रधान मंत्री किसान योजना में हो रहे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार सभी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण करते समय अपने राशन कार्ड की जानकारी भी साझा करनी होगी। अब जब आप योजना के लिए पंजीकरण करेंगे तो आपको अपने राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानि आप अपना राशन कार्ड फ़ोन के माधियम से भी दिखा सकते हो पीएम किसान पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने योजना का ई-केवाईसी करना भी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, सरकार ने जमीन की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य की हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। आपको पीएम किसान का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने सभी दस्तावेज जमा कर देंगे और उनका सत्यापन हो जाएगा।

पीएम किसान योजना के तहत , केवल एक निश्चित श्रेणी के किसानों को लाभ मिलता है। हालांकि, राज्यों ने कई धोखाधड़ी करने वालों की सूचना दी है जिन्होंने योजना के तहत लाभ का दावा किया है और प्रति वर्ष 6,000 रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया है। पीएम किसान के पंजीकरण में और अधिक घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए , किसानों को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड नंबर साझा करने होंगे। किसी भी सरकारी योजना का एक निश्चित पात्रता मानदंड होता है, जिसके आधार पर लाभ जारी किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के लिए, मॉल और सीमांत किसान जो भारतीय नागरिक हैं, पात्र हैं। इसके अलावा, सभी भूमि धारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, अब आपको योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीएम-किसान eKYC करने की आवश्यकता है।सरकार ने पीएम किसान का लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए योग्य किसानों द्वारा ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। "ईकेवाईसी पीएम-किसान पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएम-किसान पोर्टल पर उपलब्ध है,₹ वेबसाइट पर एक नोट कहता है। पीएम किसान ईकेवाईसी को पूरा करने की समय सीमा इस साल 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, आपको इसे प्राप्त जारी रखने के लिए इसे जल्द से जल्द करना चाहिए।

पुलिस बनाती रही वीडियो घायल सिपाही ने तोड़ा दम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादूनः रविवार रात को उत्तराखंड पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया. चीता पुलिस के दो कांस्टेबलों की वजह से सड़क हादसे में घायल हुए एक सिपाही की मौत हो गई. यदि चीता पुलिस के जवान थोड़ी सी मानवता दिखाते तो शायद कांस्टेबल राकेश राठौर की जान बच जाती . हालांकि इस मामले में अब देहरादून एसएसपी और डीजीपी अशोक कुमार जांच कराने की बात कह रहे हैं. दरअसल, देर रात को देहरादून पुलिस लाइन में तैनात सिपाही राकेश राठौर बाइक पर हरिद्वार से देहरादून की तरफ आ रहे थे. तभी बीच रास्ते में हर्रावाला के पास सिपाही राकेश राठौर की बाइक डिवाइडर से टकरा जाती है, जिससे राकेश राठौर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. मामले की जानकारी मिलते ही चीता पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को कॉल किया.सिपाही राकेश राठौर सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन चीता पुलिस के जवान उसे पानी पिलाने या फिर उसकी मदद करने के बजाए उसका वीडियो बना रहे थे और एंबुलेंस का इंतजार कर रहे थे. लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की.हालांकि बाद में एंबुलेंस के जरिए राकेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यहां सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यदि चीता पुलिस के जवान समय रहते राकेश को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते तो शायद उसकी जान बच सकती थी. लेकिन पुलिस उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाती रही थी.वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और देहरादून एसएसपी ने एसपी सिटी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं. वहीं डीजीपी अशोक कुमार का भी इस मामले पर बयान आया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है. जांच में यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नया लेबर कोड : हफ्ते में चार दिन काम, तीन दिन आराम !

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नया लेबर कोड लागू होने के बाद कई नियम बदलेंगे। वेतन, पेंशन, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी, छुट्टियां और यहां तक कि पूर्ण और अंतिम निपटान। केंद्र सरकार ने चार नए श्रम संहिताओं का मसौदा तैयार किया है और उन्हें संसद में पारित किया है। राज्य अब इस कोड को अपने दम पर लागू करेंगे। कुछ राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है और कुछ प्रक्रिया में हैं। नए श्रम संहिताओं में शामिल वेतन कोड इंगित करता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को कब भुगतान करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कर्मचारी के कंपनी छोड़ने या निकाल दिए जाने के कई दिनों बाद एक पूर्ण और अंतिम समझौता किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से..

वर्तमान में वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत कर्मचारियों के वेतन और वेतन के भुगतान का प्रावधान है। इसमें सेलेरी के तहत सभी तरह के भत्ते और बोनस शामिल हैं। नियम में कहा गया है कि वेतन की तारीख कंपनी और कर्मचारियों के बीच रोजगार की अवधि से निर्धारित होती है। अगर कंपनी 1 तारीख को वेतन की तारीख तय करती है, तो उसी दिन वेतन खाते में आ जाएगा। अगर कोई और तारीख तय होती है तो उस तारीख को वेतन मिलेगा।पिछले नियम में मजदूरी की सीमा 24,000 रुपये रखी गई थी। यानी उस वेतन से कम आय वालों को वेतन रोजगार की अवधि के अनुसार रखा जाएगा।

नए श्रम संहिताओं के वेतन नियम में वेतन की कोई सीमा नहीं है। और यह नियम सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि वेतन जो भी हो, कंपनी कर्मचारियों को रोजगार की अवधि के अनुसार एक निश्चित तिथि पर भुगतान करेगी। यह तारीख कंपनी और कर्मचारियों के बीच के कार्यकाल में तय की जाएगी। हालांकि नई ज्वाइनिंग वाले कर्मचारियों के लिए सेलेरी को खास नियम बनाया गया है। नई श्रम संहिताओं के अनुसार यदि कोई नई ज्वाइनिंग है तो उसका वेतन अगले माह की 7 तारीख तक तय कर लेना चाहिए। इस स्थिति में मजदूरी की अवधि एक महीने से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपको 5 जून को अजवाइन मिलती है, तो आपको इसे 5 जुलाई तक मिलनी चाहिए। 6 तारीख को ज्वाइन वेतन नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

जब छोड़ने या निकाल दिए जाने के बाद पूर्ण और अंतिम निपटान की बात आती है, तो नए श्रम संहिताओं में नियम बदल दिया गया है। फिलहाल अधिकतम 45 दिन का समय लिया गया है, इस दौरान कंपनी कर्मचारी को पूरा और फाइनल सेटलमेंट देती है। लेकिन अंतिम समझौता नया श्रम संहिता 2019 लागू होने के दो दिन के भीतर देना होगा। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 वर्तमान में लागू है। जिसने अंतिम निपटान के लिए कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया है। कंपनी एक महीने से लेकर 45 दिनों तक का समय लेती है और कर्मचारी को एक पूर्ण और अंतिम समझौता देती है

तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर केदारनाथ धाम में मानसून में भी जारी रहेंगी हेली सेवाएं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

30 जून के बाद हिमालयन कंपनी की ओर से मानसून के दौरान केदारनाथ में दी जाएगी हेली सेवाएंमानसून के मौसम में हेली सेवा से केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। तीर्थयात्री मानसून में भी हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए 30 जून के बाद केदारनाथ धाम में हिमालय कंपनी की ओर से श्रद्धालुओं को हेली सेवाएं दी जाएंगी। जबकि 05 जुलाई तक आर्यन एविएशन की ओर से केदारनाथ धाम में हेली सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने कहा कि इससे पहले हेली कंपनियों द्वारा मानसून के दौरान सामान्यता केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बंद कर दी जाती थी। ऐसे में यह एक सकारात्मक कदम हैं कि बरसात के दिनों में भी तीर्थयात्रियों को हेली सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका सीधा लाभ बरसात के मौसम में केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेली सेवा के लिए आवश्यक मानकों का पालन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम जाने के लिए तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, फाटा और सिरसा से हेली सेवा की सुविधा दी जाती है। यहां नौ कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जाती है। पहली बार इस साल मानसून में भी श्रद्धालुओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। हिमालयन कंपनी की ओर से मानसून के दौरान उड़ान भरने के लिए मौसम अनुकूल रहने की दशा में एक दिन में 30-40 शटल संचालित की जाएंगी। इसमें प्रतिदिन करीब 200 से 250 तीर्थयात्री लाभान्वित होंगे।

अक्टूबर से उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को होगी तकलीफ दिल्ली सरकार ने भेजा पत्र

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

एक अक्टूबर के बादउत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज की 250 में से 200 बसों पर लग जाएंगे ब्रेक। दरअसल, केवल बीएस-6 बसों को ही मिलेगी एंट्री। बीएस-6 क्या होता है ? भारत स्टेज 6 (BS VI) एक उत्सर्जन मानक है। भारत चरण (बीएस) मानदंड भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए स्थापित किए गए उत्सर्जन मानक हैं।

हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त ओपी मिश्रा की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को एक पत्र मिला है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर से दिल्ली में किसी भी राज्य की बीएस-4 बस को एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल बीएस-6 रोडवेज बसें ही एंट्री कर सकेंगी। इसके अलावा, एनजीटी ने पहले ही निर्देश दिया है कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने सिर्फ बीएस-6 बसों को ही एंट्री देने का पत्र भेजा है। बीएस-6 मानक वाली 22 वॉल्वो और कुछ अनुबंधित बसें मिलाकर सिर्फ 50 बसें ही परिवहन निगम के पास हैं पत्र में बताया गया है कि दिल्ली का पूरा सार्वजनिक परिवहन सीएनजी आधारित हो चुका है। लिहाजा, एक अक्टूबर से दिल्ली में किसी भी राज्य की बीएस-4 बस को एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल बीएस-6 रोडवेज बसें ही एंट्री कर सकेंगी।इस पत्र के बाद परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निगम की करीब 250 बसें उत्तराखंड से दिल्ली रूट पर संचालित होती हैं। इनमें से बमुश्किल 22 वॉल्वो और कुछ अनुबंधित मिलाकर 50 बसें ही बीएस-6 हैं। इसके लिए निगम अब 141 बीएस-6 बसें खरीदने जा रहा है, जिसका टेंडर निकल चुका है। उम्मीद है, उससे पहले ही हम इस समस्या से पार पा लेंगे।

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के छात्राओं ने वालीबॉल प्रीमियर लीग में दिखाई प्रतिभा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। जिसमें प्रथम चरण में गर्ल्स टीम का फाइनल मैच का समापन 28 जून की को शाम को किया गया। प्राचार्य डॉ प्रोफेसर आशुतोष सयाना, डॉ अशोक कुमार एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर सुशील ओझा एसोसिएट प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग, डॉक्टर अनुपमा आर्य एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर अनिल जोशी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग एवं डॉ अभय कुमार एसोसिएट प्रोफेसर शल्य चिकित्सा विभाग ने पहुंचकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉ आशुतोष सयाना ने विजय और उप विजेता टीम को टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया। साथ में प्राचार्य ने खेल का महत्व समझाया। कहा खेलने से ना केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है और एक टीम में कार्य करने की भावना का भी जागरण होता है, जो कि एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि नए सीबीएमई पाठ्यक्रम में भी टीम में काम करने को सिखाने के लिए खेल द्वारा उत्साहवर्धन का प्रावधान किया गया है एवं नए पाठ्यक्रम में यह योगा को भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है।

उत्तराखंड सरकार में ओएसडी बने पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे, बदरीनाथ-केदारनाथ के पुनर्निर्माण की मिली कमान

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री के बदरीनाथ व केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्टों की कमान सौंपी गई है। प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते भास्कर खुल्बे केदारनाथ और बदरीनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे हैं। वे कुछ दिनों से उत्तराखंड प्रवास पर थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु से शिष्टाचार भेंट की थी। इन मुलाकातों के बाद सचिवालय के गलियारों में खुल्बे को प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। दिन में ही यह चर्चा गर्म थी कि उन्हें उत्तराखंड में रहते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देर शाम उन्हें पर्यटन विभाग में ओएसडी बनाए जाने के आदेश भी जारी हो गए।

कौन हैं आईएएस भास्कर खुल्बे : भास्कर खुल्बे ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर से 1979 में जूलॉजी से एमएससी की थी। भास्कर का चयन भारतीय सेना में अधिकारी के पद के लिए हो गया था। उन्होंने छह माह तक ट्रेनिंग भी की लेकिन मेडिकल कारण से उन्हें वापस आना पड़ा। भास्कर ने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रो. जेएस बिष्ट के निर्देशन में पीएचडी शुरू कर दी थी। 1982 में उनका चयन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हो गया था और इसमें वह अखिल भारतीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहे थे। आईएफएस की ट्रेनिंग के दौरान भी वे पढ़ाई में लगे रहे और अंततः उनका चयन आईएएस में हो गया। उनकी योग्यता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें पीएमओ में महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई थी।

फिल्म, TV और Reality Shows में बाल कलाकारों के लिए आ गयी आयोग की गाइडलाइन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रियलिटी शोज और सोशल मीडिया के लिए तैयार होने वाले वीडियोज में बच्चों के शोषण और उनसे करवाए जाने वाले उटपटांग कामों पर अब रोक लगने की उम्मीद है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने मनोरंजन उद्योग में बच्चों के काम-काज से जुड़ी गाइडलाइन तैयार कर ली है।

मनोरंजन के नाम पर बच्चों से फूहड़ सीन करवाना या खतरनाक और उटपटांग काम में लगाए रखना अब मुश्किल होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को मनोरंजन उद्योग में बच्चों के काम-काज से जुड़ी नई गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर जारी कर दिया है। अब जल्दी ही इसे वैधानिक रूप मिल सकेगा। 'मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण' GUIDELINES FOR CHILD PARTICIPATION IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY नाम से जारी इस गाइडलाइन के मसौदे में बाल कलाकारों के अधिकारों को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है।

बच्चों से अश्लीलता के सीन कतई नहीं

इसमें कहा गया है कि हर बाल कलाकार को आत्म सम्मान के साथ काम करने और उससे जुड़े फैसलों में भाग लेने का अधिकार होगा। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। उससे ऐसा कोई रोल नहीं करवाया जा सकेगा जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े या उसे भावनात्मक चोट पहुंचे। इन दिनों रियलिटी शोज में जज अक्सर भाग लेने वालों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। इस तरह के व्यवहार की नई गाइडलाइन में साफ मनाही की गई है। यह कहती है कि बच्चों से किसी भी तरह के नग्नता या अश्लीलता के सीन नहीं करवाए जा सकते।

Child artist के साथ गार्जियन रहे मौजूद

आयोग की गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कलाकार 6 साल से कम उम्र का है तो हर समय उसके साथ मां-बाप में से एक व्यक्ति या उसका लीगल गार्जियन मौजूद रहे। इसी तरह 6 साल से बड़े बच्चों के साथ भी गार्जियन या उसके किसी परिचित का मौजूद रहना जरूरी होगा। बाल कलाकारों से एक दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करवाया जा सकेगा। साथ ही हर तीन घंटे के बाद उन्हें ब्रेक देना पड़ेगा।

बच्चों से अश्लीलता के सीन कतई नहीं

इसमें कहा गया है कि हर बाल कलाकार को आत्म सम्मान के साथ काम करने और उससे जुड़े फैसलों में भाग लेने का अधिकार होगा। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। उससे ऐसा कोई रोल नहीं करवाया जा सकेगा जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े या उसे भावनात्मक चोट पहुंचे। इन दिनों रियलिटी शोज में जज अक्सर भाग लेने वालों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। इस तरह के व्यवहार की नई गाइडलाइन में साफ मनाही की गई है। यह कहती है कि बच्चों से किसी भी तरह के नग्नता या अश्लीलता के सीन नहीं करवाए जा सकते।

Child artist के साथ गार्जियन रहे मौजूद

आयोग की गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कलाकार 6 साल से कम उम्र का है तो हर समय उसके साथ मां-बाप में से एक व्यक्ति या उसका लीगल गार्जियन मौजूद रहे। इसी तरह 6 साल से बड़े बच्चों के साथ भी गार्जियन या उसके किसी परिचित का मौजूद रहना जरूरी होगा। बाल कलाकारों से एक दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करवाया जा सकेगा। साथ ही हर तीन घंटे के बाद उन्हें ब्रेक देना पड़ेगा।

जुलाई में 16 दिनों के लिए बैंक रहेंगे बंद यहां चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर आप जुलाई में बैंक संबंधी जरूरी कार्य करने की सोच रहे हैं तो पहले हमारी ये खबर पढ़ लीजिये। जी हाँ अगर आप भी अगले महीने बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको जान लेने चाहिए कि उस दिन आपका बैंक खुला रहेगा या नहीं? अगले महीने जुलाई 2022 में देश के बैंक आधे से अधिक महीने के लिए बंद रहने वाले हैं। न्यूज़ वायरस आपको बता रहा है कि किस-किस दिन पड़ रहीं छुट्टियां...बैंक की छुट्टियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से चार श्रेणियों के तहत तय की जाती हैं। रिजर्व बैंक ने जुलाई माह के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार, जुलाई 2022 में शनिवार और रविवार के सात अवकाश पड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, कुछ राज्यवार अवकाश भी दिए जा रहे हैं।आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार, विभिन्न कारणों से बैंक बंद रहेंगे। इन अवकाश के तहत सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों की सभी शाखाएं बंद रहेंगी। ये सभी छुट्टियां अलग-अलग जगहों के लिए भिन्न-भिन्न कारणों से होंगी। कई बैंक अवकाश विशेष अवसरों और राज्य-विशिष्ट त्योहारों के तहत लागू होंगे।यहां देखें जुलाई 2022 के लिए बैंक अवकाश की लिस्ट

1 जुलाई (शुक्रवार): रथ यात्रा (ओडिशा)

6 जुलाई (बुधवार): एमएचआईपी दिवस (मिजोरम)

5 जुलाई (मंगलवार) : गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन (जम्मू और कश्मीर)

7 जुलाई (गुरुवार): खारची पूजा (त्रिपुरा)

9 जुलाई (शनिवार): ईद-उल-अधा (बकरीद)/ दूसरा शनिवार

11 जुलाई (सोमवार): ईद-उल-अजहा (जम्मू और कश्मीर)

13 जुलाई (बुधवार): भानु जयंती (सिक्किम)

14 जुलाई (गुरुवार): बेन डिएनखलम (मेघालय)

16 जुलाई (शनिवार): हरेला (उत्तराखंड)

23 जुलाई (शनिवार): चौथा शनिवार

26 जुलाई (मंगलवार): केर पूजा (त्रिपुरा)रविवार: 3 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 31 जुलाई

पुलिस सैलरी पैकेज योजना उत्तराखंड पुलिस के लिए बनी वरदान - PNB ने सौंपा 50 लाख का चेक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की उपस्थिति में संजय काण्डपाल, जोनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक देहरादून जोन द्वारा रक्षक प्लस योजना के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले जनपद देहरादून में तैनात ओ0पी0 विजय चौहान की पत्नी श्रीमती ममता चौहान को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से 50 लाख रूपए का चेक दिया गया।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि 2019 में उत्तराखण्ड पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़े कल्याणकारी कदम के रूप में उत्तराखण्ड पुलिस तथा पंजाब नेशनल बैंक के बीच पुलिस सैलरी पैकज के लिए समझौता (एम.ओ.यू.) किया गया था, जिसके अन्तर्गत जिन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन पंजाब नेशनल बैंक में आहरित हो रहा है उनको रक्षक प्लस योजना के अन्तर्गत बिना प्रीमियम जमा किए दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा था वर्ष 2021 में एम.ओ.यू. का नवीनीकरण कर इस बीमा कवर को बढ़ाकर 50 लाख रूपए कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019 से अब तक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 15 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बीमा कवर की राशि प्रदान की गयी है।

पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी वर्ष 2018 में समझौता (एम.ओ.यू.) किया गया था, जिसके अन्तर्गत बिना प्रीमियम जमा किए दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर 25 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा था। वर्ष 2021 में एम.ओ.यू. का नवीनीकरण कर इस बीमा कवर को बढ़ाकर 50 लाख रूपए कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 से अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 09 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बीमा कवर की राशि प्रदान की गयी है।पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 24 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बीमा कवर की राशि प्रदान की गयी है।

संपादकीय

जी-7 में प्रधानमंत्री

जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे विकसित सात देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान- के महत्वपूर्ण शिखर बैठक में कुछ अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भागीदारी की है. वर्ष 2014 से उन्हें तीन बार इस समूह की बैठक में आमंत्रित किया जा चुका है. यह निश्चित ही वैश्विक समुदाय में भारत के बढ़ते महत्व का परिचायक है. जी-7 के नेताओं के साथ-साथ अन्य आमंत्रित देशों- अर्जेंटीना, सेनेगल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी वार्ताएं कर रहे हैं. इस बैठक में यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी हिस्सा ले रहे हैं. इस शक्तिशाली समूह द्वारा भारत को आमंत्रित किया जाना इस बात का सूचक है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं भारत को एक निकट सहयोगी के रूप में देखने के साथ वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उसकी उल्लेखनीय भूमिका को भी स्वीकार करती हैं. भारत न केवल जी-7 की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है, बल्कि वह क्वाड, आई2यूटू, ब्रिक्स आदि समूहों का भी सदस्य है. हाल के समय में विदेश मंत्री समेत कई भारतीय कूटनीतिकों ने विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं तथा अनेक देशों के नेताओं ने भी भारत का दौरा किया है. इससे स्पष्ट है कि आज भारत की वैश्विक प्रासंगिकता स्थापित हो चुकी है. महामारी, आपूर्ति शृंखला में अवरोध, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भू-राजनीति में हलचल के इस दौर में भारत अपने राष्ट्रीय हितों तथा वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए लगातार प्रयासरत है. जी-7 की बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध तथा इससे उत्पन्न ऊर्जा और खाद्य संकट पर केंद्रित है. भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं. यद्यपि भारत ने रूस के हमले को सही नहीं ठहराया और बातचीत से तनाव खत्म करने की पैरोकारी की, पर पश्चिमी देश इससे संतुष्ट नहीं थे. युद्ध के प्रारंभिक दिनों में रूस की निंदा करने और पश्चिम का साथ देने के लिए भारत पर बड़ा दबाव था. पर भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम अपने राष्ट्रहित और रणनीतिक हितों के अनुरूप चलेंगे. इस आमंत्रण से ऐसा प्रतीत होता है कि जी-7 के सदस्य देश भारत की समझ से संतुष्ट है. भारत द्वारा अनाज मुहैया कराने का मुद्दा भी इस आयोजन में बातचीत का एक हिस्सा हो सकता है. बहरहाल, यह घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा मुद्रास्फीति रोकने से जुड़ा एक तात्कालिक उपाय है. मुख्य बात यह है कि अनेक मुद्दों पर असहमतियों के बावजूद विकसित देश यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया के सामने खड़ीं चुनौतियों का सामना करने में भारत को साथ लेना ही होगा. विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के अलावा सबसे अहम मसला जलवायु संकट से संबद्ध है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भारत के अनुभवों और योजनाओं को बैठक में रखा है.

दुःखद : नहीं रहे उत्तराखंड के प्रतिभाशाली कलाकार नवीन सेमवाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हाल ही में उत्तराखंड के म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा जब बेहद पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर और युवा कलाकार गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हुआ था।

इस बुरी खबर को ज्यादा समय नहीं हुआ था और इससे उत्तराखंड उभर ही रहा था कि उत्तराखंड को दोबारा से एक बड़ा झटका लग गया है। उत्तराखंड के बहु प्रतिभावान कलाकार नवीन सेमवाल का आज सुबद निधन हो गया है। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, आज अचानक उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है, हर कोई निशब्द है, नवीन सेमवाल की शुरुआती तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उनके निवास स्थान रुद्रप्रयाग में स्थित राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार ना देखते हुए उन्हें देहरादून के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बामणी जैसे सुपरहिट गढ़वाली गाने में अपनी आवाज देने वाले गायक, रंगकर्मी नवीन सेमवाल ने मंगलवार सुबह आखिरी सांसें लीं. उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है।

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में दिखा बारिश का कहर, बहा तीन गांवों को जोड़ने वाला पैदल पुल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मॉनसून ने अभी पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन बरसात से नुकसान पहले दिन से ही दिखने लग गया. भारी बारिश के कारण दूरस्थ क्षेत्र थलीसैंण ब्लाक के चाकीसैंण तहसील के अन्तर्गत सुनारगांव समेत तीन गांवों को जोड़ने वाला पैदल पुल बहा. जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.मूसलाधार बारिश से पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई और उसके तेज बहाव में पुल पूरी तरह टूट गया है. उन्होंने बताया कि पुल के टूटने से तीनों गांवों के करीब 80 से अधिक परिवार प्रभावित हो गए हैं. यही नहीं कई गांवों में भूमि कटाव से खेती को भी नुकसान पहुंचा है. इस पुल से क्षेत्र के सुनारगांव, कृषाल व कठूड़ के ग्रामीण आवाजाही करते थे.वहीं तीन गांवों के परिवारो को कच्चे पैदल पुल से आना जाना करना पड़ रहा है. जिले के दूरस्थ क्षेत्र थलीसैंण ब्लाक के चाकीसैंण तहसील के अन्तर्गत हुई पांच घंटे की मूसलाधार बारिश से पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई. जिससे तीन गांवों की आवाजाही का आधार सुनारगांव पैदल पुल पूरी तरह टूट गया है. तहसील प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का आकलन कर रही है. क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भरत सहि पंवार ने बताया कि महाविद्यालय मजरा महादेव के समीप पश्चिमी नयार नदी पर एक पैदल पुल साल 2014 में बनाया गया था.इस पुल से क्षेत्र के सुनारगांव, कृषाल व कठूड़ के ग्रामीण आवाजाही करते थे. लेकिन मूसलाधार बारिश से पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई और उसके तेज बहाव में पुल पूरी तरह टूट गया है. उन्होंने बताया कि पुल के टूटने से तीनों गांवों के करीब 80 से अधिक परिवार प्रभावित हो गए हैं. यही नहीं कई गांवों में भूमि कटाव से खेती को भी नुकसान पहुंचा है.उपजिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवांठा ने कहा जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को समय रहते ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए गए हैं।

बादाम के स्वास्थ्य लाभ और जानिए क्यों बोलते है, उसे सुपरफूड

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हम चमत्कारिक खाद्य पदार्थों के युग में रहते हैं जहाँ कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में माना जाता है कि उनमें जादुई गुण होते हैं और उन्हें नियमित रूप से खाने से अधिकांश स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ ठीक हो जाती हैं। दुर्भाग्य से, यह सच नहीं है। कोई चमत्कारिक खाद्य पदार्थ नहीं हैं जो बीमारी को स्वयं रोक सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। हालांकि, बादाम जैसे कुछ पोषक तत्व-घने खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपरफूड का दर्जा दिया जा सकता है। चाहे साबुत खाया जाए, कटा हुआ, या आटे में कुचला गया हो, बादाम एक पंच पैक करते हैं।

बादाम के 3 फायदों के बारे में बताया है।बादाम में प्रोटीन और फाइबर काफी होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है और और अस्वस्थ चीजें खाने की आशंका कम कर देता है। इसके अलावा बादाम खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता जाता है और शरीर तेजी से फैट बर्न करता है। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। जो कि आपकी दिमागी क्षमता बढ़ाता है। खैर,ये सब तो अपने सुन हे रखा है। अब बताते है आपको कुछ नई फायदे के बारे में.1) बादाम में मैग्नीशियम होता है, जो रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है, बादाम कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार कर सकता है2) बादाम फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं लेकिन कार्ब्स में कम होते हैं। इन गुणों के कारण, वे भूख को कम करने और भूख को संतुष्ट करने में अच्छे हैं। 3) बादाम को विटामिन बी-6 के स्रोत के साथ सबसे अच्छा जोड़ा जाता है, जैसे कि केला, क्योंकि वे ट्रिप्टोफैन में उच्च होते हैं।

ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में परिवर्तित करके अवसाद के लक्षणों को कम करने के लिए विटामिन बी 6 पाया गया है।4) बादाम कोलेस्ट्रॉल में सुधार कर सकता हैबादाम के इन फायदों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने नियमित आहार में शामिल करें। वे इतने बहुमुखी हैं कि आप उन्हें विभिन्न तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

आठ सीटों वाले वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य : केंद्रीय मंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार 'इंटेल इंडियाज सेफ्टी पायनियर्स कॉन्फ्रेंस 2022' को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कार निर्माताओं के लिए मोटर आठ सीटों वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग देना अनिवार्य करेगी, जिसमें सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आठ यात्री सवार हो सकते हैं। हर साल देश भर में पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, ₹हमने मोटर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग देना अनिवार्य करने का फैसला लिया है। हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। ₹सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जनवरी में कहा कि पार्श्व प्रभाव के खिलाफ मोटर वाहनों में रहने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

एयरबैग एक वाहन अधिभोगी-संयम प्रणाली है जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच हस्तक्षेप करती है, जिससे गंभीर चोटों को रोका जा सकता है।₹14 जनवरी, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहनों को दो साइड / साइड टोरसो एयर बैग से सुसज्जित किया जाएगा, आगे बैठने वालो प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्रंट रो पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक पोजीशन, और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, एक-एक आउटबोर्ड पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए, "यह कहा था।सरकारी सूत्रों के अनुसार चार अतिरिक्त एयरबैग लगाने की लागत 9,000 रुपये से 10,000 रुपये होगी। प्रत्येक एयरबैग की कीमत 1,800 रुपये से 2,000 रुपये के बीच है, और वाहन को संशोधित करने की लागत 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच होगी। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि चार और एयरबैग फिट करने के लिए वाहन को संशोधित करना एक चुनौती हो सकती है।

बला की खूबसूरत है 'मंत्री जी' की बीवी - दिल थम कर देखिये तस्वीरें

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सेलेब्रिटीज़ और उनकी फैमली हमेशा प्रशंसकों के लिए रोचक और कौतुहल का विषय होती हैं। अगर बात राजनीती की करें तो चुनिंदा नेता ऐसे भी हैं जिनकी पत्नियां बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को खूबसूरती में पछाड़ रही हैं। ऐसी ही एक मैडम हैं सुष्मिता जिनकी तस्वीरें देख कर आप भी कहेंगे बीवी हो तो ऐसी हम बात कर रहे हैं बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी की जो अक्सर सूर्खियों में रहते हैं। हाल ही में रणजी में शतक जमाने के बाद उन्होंने अपना लव लेटर लहराया जिसमें लिखा- आई लव यू सुष्मिता। मनोज तिवारी के साथ उनकी पत्नी सुष्मिता भी अपनी खूबसूरती के कारण सोशल मीडिया पर छाईं रहती हैं।मनोज तिवारी एक ऐसा नाम है जो भारतीय क्रिकेट में बेहद बदकिस्मत रहा है। कभी कभी अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उन्हें चयनकर्ताओं ने टीम में नहीं चुना। 2008 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उनका प्रदर्शन सही नहीं रहा था इसलिए उन्हें तीन वर्षों तक किसी भी मैच में नहीं लिया गया! मनोज ने फिर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी वापसी की लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया

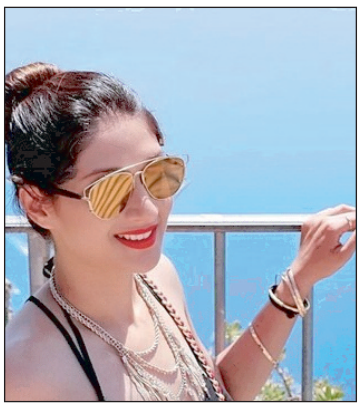

में वह अपनी जगह नहीं बना पाए।

भारतीय क्रिकेटर्स और उनकी खूबसूरत पत्निया अक्सर चर्चा में रहती है। चाहे वह विराट कोहली-अनुष्का शर्मा हो या रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका और अब मनोज तिवारी और सुष्मिता की जोड़ी की काफी चर्चा होने लगी है !मनोज तिवारी और सुष्मिता राय बचपन से ही दोस्त थे और दोस्ती कब प्यार में बदली पता न चला..लेकिन मनोज तिवारी ने एक ऐसी लड़की के दिल में जरूर अपनी जगह बनायीं जो बचपन से उनकी दोस्त थी! टीम इंडिया के खिलाडी अपने शानदार प्रदर्शन की वजह मीडिया में छाए रहते हैं, शायद ही कोई क्रिकेटर अब ऐसा होगा जो स्टाइलिश ना हो, सभी बड़े बंगलो में रहते है अच्छी महंगी गाड़िया चलते है और स्टाइलिश कपडे पेहेनते है! जब क्रिकेटर इतने स्टाइल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत लड़किया उनकी फैंस बनती है और उनकी तरफ आकर्षित भी होती है !मनोज की पत्नी सुष्मिता राय भी अपनी खूबसूरती की वजह से काफी चर्चा में रहती है और लोग इनकी तुलना बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से करते है। मनोज तिवारी और सुष्मिता राय बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे जो समय के साथ प्यार में तब्दील हो गया! सुष्मिता अपने करियर के शुरुआती दिनों में मॉडलिंग करती थी और साल 2013 में दोनों ने शादी करली ! सुष्मिता ने अपने मॉडलिंग करियर को शादी के बाद पीछे छोड़ दिया था और शादी के बाद परिवार की सारी ज़िम्मेदारिया अपने कंधो पर उठा ली थी! साल 2018 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसके साथ अब दोनों खुश है! मनोज और सुष्मिता दोनों बंगाल से है लेकिन उन्होंने शादी पुरे UP स्टाइल में की थी!

सांगली में 9 लोगों की खुदकुशी का केस, पुलिस की जांच में सामने आया है कि मौत की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

20 जून को महाराष्ट्र के सांगली जिले में करीब एक हफ्ते पहले पुलिस ने एक ही परिवार के नौ शव बरामद किए थे. बता दे की मृतकों में दो भाई और उनके परिवार के सात सदस्य शामिल हैं, जो अपने घरों में मृत पाए गए थे। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि जहर खाकर परिवार ने आत्महत्या की है।पुलिस ने अब परिणाम निकाला है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि परिवार के सदस्यों को वास्तव में जहर देकर मार डाला गया था और पुलिस ने 'हत्या' के सिलसिले में सोलापुर से दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दो लोगों ने भोजन या पेय-पदार्थ के माध्यम से परिवार के सदस्यों को जहर दिया।

दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद

बगवान और धीरज सुरवासे के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने छिपे हुए खजाने को खोजने में मदद करने के बहाने दोनों भाइयों से एक करोड़ रुपये लिए थे। छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए भाइयों ने आरोपी को भुगतान करने के लिए 1 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई खजाना नहीं है, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। इसलिए पैसे वापस करने से बचने के लिए आरोपी ने परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रची।पोपट और माणिक वानमोर के परिवार के सात सदस्यों के शव एक-दूसरे से आधा किलोमीटर दूर स्थित उनके घरों से मिले। पोपट एक शिक्षक के रूप में काम करते थे, जबकि उनके भाई वनमोर एक पशु चिकित्सक थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।

सांगली के एसपी दीक्षित कुमार गेदम के अनुसार, दोनों तथाकथित छिपे हुए खजाने के बारे में परिवार का मार्गदर्शन करते थे। "19 जून को, वे परिवार के घरों में गए और खाने-पीने में जहर मिलाया। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा